Import of Gas

259. SHRI IQBAL SINGH: Will the Minister of PETROLEUM AND NATURAL GAS be pleased to state:

(a) whether Government are considering to import gas from Myanmar, Indonesia, Qatar and other countries;

(b) if so, the details thereof country-wise and reasons therefor; and

(c) the steps being taken by Government to fulfil the gap between demand and supply of petroleum products in the country?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF PETROLEUM AND NATURAL GAS (CAPT. SATISH SHARMA): (a) and (b) Myanmar, Indonesia and Qatar are possible sources of natural gas/LNG. Accordingly, the Government is examining the feasibility of importing natural gas/LNG from these countries.

(c) The current gap between demand and supply of petroleum products in the country is being met through imports. Government has also taken several measures to augment the indigenous production of oil and gas. Government has also allowed private investment in the oil refining sector to increase refining capacity in the country. For improving the supply of LPG and Kerosene, parallel marketing of imported LPG and Kerosene at market related prices has also been introduced by Government.

LPG Connections on the Recommendations of MPs and others

260. SHRI SHIV CHARAN SINGH: Will the Minister of PETROLEUM AND NATURAL GAS be pleased to state:

(a) the total number of LPG connections granted to consumers on an out of turn priority basis (i) on the recommendations of MPs (ii) others and (iii) of his own during the current financial year with regard to U.P. and Rajasthan; and

(b) what are the details of MPs who have recommended for such connections over and above their stipulated quotas/ coupons alongwith the number of such accepted recommendations during the current year?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF PETROLEUM AND NATURAL GAS (CAPT. SATISH SHARMA): (a) and (b) Ministry of Petroleum and Natural Gas have issued orders to the LPG Marketing Companies to release 123219 domestic LPG connections on out of turn basis during the period 1.1.1995 to 31.12.1995. These connections have been sanctioned on the requests of individuals and recommendations of public representatives, including MPs and Ex-MPs in urgent and deserving cases at the discretion of the Government. The efforts involved in compiling the information as to whom these connections have been given and at whose recommendation will not be commensurate with the objective sought to be achieved. Out-of-turn LPG connections are not given on State-wise basis.

डाक घर रहित गांव

261. **श्री कनकसिंह मोहनसिंह मंगरोला:** क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने कतिपय राज्यों के उन गांवों के संबंध में कोई सर्वेक्षण किया है जिनमें इस समय कोई डाक व तार घर नहीं है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने इन राज्यों के सभी गांवों में डाक व तार घर खोलने का विचार रखती है;

(घ) आज की तारीख तक किस-किस राज्यों ने इस संबंध में प्रस्ताव प्रस्तुत किए हैं; और

(ङ) क्या सरकार को ऐसे गांवों में डाक व तार संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए

चलते-फिरते डाक घर अथवा स्थानीय सुविधाओं के लिए प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुख राम): (क) ऐसे गांवों के संबंध में सरकार ने अलग से कोई विशेष सर्वेक्षण नहीं किया है जिनमें इस समय डाक घर और तार घर की सुविधाएं नहीं हैं।

(ख) उपर्युक्त (क) को ध्यान में रखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

(ग) **डाक घर:** डाकघर योजना स्कीमों के अंतर्गत उन गांवों में खोले जाते हैं जिनमें अभी तक डाकघर नहीं है। देश के गांवों में वार्षिक योजना 1995-96 के अंतर्गत 80 अतिरिक्त विभागीय शाखा डाकघर खोलने का प्रस्ताव है।

तार घर: विभाग की ऐसी कोई नीति नहीं है कि राज्यों के सभी गांवों में तार सुविधा प्रदान की जाएं। तार सेवा मांग, औचित्य तथा परियात की मात्रा के आधार पर प्रदान की जाती है।

(घ) **डाक घर:** प्रत्येक डाक सर्किल से आज तक प्राप्त हुए प्रस्तावों का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है। **(नीचे देखिए)**

(घ) ओर (ङ) **तार घर:** उपर्युक्त (ग) को ध्यान में रखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) **डाक घर:** जी नहीं।

विवरण

वार्षिक योजना 1995-96 के अंतर्गत आज की तारीख तक अतिरिक्त विभागीय शाखा डाकघर खोलने के लिए प्राप्त हुए प्रस्ताव

क्रम सं॰	डाक सर्किल का नाम	प्राप्त हुए प्रस्तावों की संख्या
1.	बिहार	—
2.	गुजरात	7
3.	हिमाचल प्रदेश	17
4.	उड़ीसा	10
5.	महाराष्ट्र	12
6.	तमिलनाडु	2
7.	उत्तर प्रदेश	5
8.	आन्ध्र प्रदेश	2
9.	असम	6
10.	दिल्ली	—
11.	हरियाणा	—
12.	कर्नाटक	1
13.	केरल	—
14.	मध्य प्रदेश	2
15.	उत्तर पूर्व	1
16.	जम्मू एवं कश्मीर	—
17.	पंजाब	2
18.	राजस्थान	5
19.	पश्चिम बंगाल	—
		72

पेप्सी कंपनी द्वारा गाय की चर्बी का कथित प्रयोग

262. **श्रीमती सुषमा स्वराज:** क्या **खाद्य प्रसंस्करण उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ध्यान 8 फरवरी, 1996 के दैनिक पायनीयर में "पेप्सी युजेज काऊ फैट इन च्युंइंग गम्स" शीर्षक के अन्तर्गत प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या यह सच है कि देश में कार्यरत बहुराष्ट्रीय कंपनी पैप्सी द्वारा अपने विभिन्न उत्पादों के निर्माण में गाय की चर्बी का उपयोग करने का समाचार सरकार के ध्यान में लाया गया है;

(ग) यदि हां, तो सरकार ने इस समाचार की जांच पड़ताल की है;

(घ) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस प्रकार की जांच पड़ताल का यह कार्य देश की किस-किस प्रयोगशाला को कब-कब सौंपा गया है;

(ङ) क्या इन अन्वेषण तथा जांच प्रयोगशालाओं ने अब अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है; और

(च) यदि हां, तो ऐसी रिपोर्टों का प्रयोगशाला-वार ब्यौरा क्या है?

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री के॰पी॰ सिंह देव): (क) जी हां।

(ख) से (च) सरकार ने च्युइंग गम्स के उत्पादन के लिए मै॰ पेप्सी फूड्स लि॰ या मै॰ पेप्सिको इंडिया